सरदार गुरमेज सिंह

बनाम

सरदार प्रताप सिंह कैरोन

(न्यायाधीशगण एस.आर. दास, एस.के. दास, ए.के. सरकार,

के. सुब्बा राव और एम. हिदायतुल्ला जेजे.)

चुनाव याचिका-मतदान के रूप में लम्बरदार की नियुक्ति और गणना अभिकर्ता-चाहे वह भ्रष्ट आचरण हो-लम्बरदार, यदि कोई ग्राम लेखाकार हो-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43), की धाराएँ 123 (7) (च)।

प्रत्यर्थी को सरहाली निर्वाचन क्षेत्र से पंजाब विधानसभा के लिए निर्वाचित घोषित किया गया था। अपीलार्थी, जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में से एक था, ने इस घोषणा के लिए एक चुनाव याचिका दायर की कि प्रतिवादी का चुनाव अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर अमान्य था कि उसने कई लाम्बारदारों को अपने मतदान और गिनती एजेंटों के रूप में नियुक्त किया था और इस प्रकार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (7) में उल्लिखित एक भ्रष्ट प्रथा को अंजाम दिया था। अपीलार्थी ने तर्क दिया कि लैम्बरदार धारा 123 (7) के खंड (च) के अर्थ के भीतर राजस्व अधिकारी और ग्राम लेखाकार दोनों थे।

अभिनिर्धारित किया गया कि लाम्बारदार अधिनियम की धारा 123 (7) के खंड (च) के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति नहीं थे और तदनुसार प्रत्यर्थी ने लाम्बारदार को अपने मतदान और गणना एजेंट के रूप में नियुक्त करने में कोई भ्रष्ट प्रथा नहीं की थी। धारा 123 (7) के खंड (च) में राजस्व अधिकारियों को संदर्भित किया गया है, जिसमें ग्राम लेखाकार जैसे पटवाड़ी, लेखपाल, कर्णम आदि शामिल हैं, लेकिन इसमें अन्य ग्राम अधिकारी शामिल नहीं हैं। वंश "राजस्व अधिकारी" है, और "सहित" और "संयोजन

द्वारा जुड़े खंडों को छोड़कर" लेकिन "यह दर्शाता है कि ग्राम लेखाकार राजस्व अधिकारियों के समूह में शामिल थे, लेकिन अन्य ग्राम अधिकारियों को इससे बाहर रखा गया था। लैम्बरदार, ग्राम राजस्व अधिकारी होने के नाते, अधिनियम की धारा 123 (7) के खंड (च) के संचालन से बाहर थे। इसके अलावा, लंबरदार ग्राम लेखाकार नहीं थे और खंड (च) के समावेशी भाग में नहीं आते थे।

राजा बहादुर के.सी. देव भंज बनाम रघुनाथ मिश्रा, 19 ई.एल.आर. I, विशिष्ट।

सिविल अपीलीय अधिकारिता : सिविल अपील संख्या 324/1959।

1959 के सिविल रिट सं. 170 में पंजाब उच्च न्यायालय के 12 मार्च, 1959 के निर्णय और आदेश से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

अपीलार्थी की ओर से एन. सी. चटर्जी और जनार्दन शर्मा।

जी.एस. पाठक, एच.एस. दोआबिया, पंजाब राज्य के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता, गोपाल सिंह और पी.एस. सफीर, प्रतिवादी की ओर से।

1959, 30 सितंबर को न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सुब्बा राव द्वारा सुनाया गया।

विशेष अनुमति द्वारा यह अपील लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा जाता है) की धारा 123 (7) के प्रावधानों के सही निर्माण का सवाल उठाती है। भौतिक तथ्यों को संक्षेप में बताया जा सकता हैः अपीलकर्ता सरदार गुरमेज सिंह, पंजाब राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री और प्रतिवादी सरदार प्रताप सिंह कैरों और अन्य फरवरी 1957 में हुए आम चुनाव में सरहाली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार थे। प्रत्यर्थी ने सबसे अधिक वोट हासिल किए और उन्हें पंजाब विधान सभा के लिए विधिवत निर्वाचित घोषित किया गया। 11 अप्रैल, 1957 को, अपीलार्थी ने इस घोषणा के लिए एक चुनाव याचिका (1957 की चुनाव याचिका

संख्या 22) दायर की कि प्रत्यर्थी का चुनाव अधिनियम की धारा 100 के तहत अमान्य था। अन्य बातों के साथ-साथ, उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि प्रत्यर्थी और उनके चुनाव एजेंट ने विभिन्न केंद्रों पर प्रत्यर्थी के गिनती और मतदान एजेंट के रूप में कई व्यक्तियों को नियुक्त किया था और यह कि उक्त व्यक्ति, भौतिक समय पर, लम्बरदार के रूप में काम कर रहे थे, और इसलिए, प्रत्यर्थी अधिनियम की धारा 123 के अर्थ के भीतर भ्रष्ट व्यवहार का दोषी था। प्रत्यर्थी ने याचिका में लगाए गए भौतिक आरोपों से इनकार किया। दलीलों पर कम से कम 12 मुद्दों को तैयार किया गया और 3 और 8 मुद्दों को प्रारंभिक मुद्दों के रूप में सुनवाई के लिए लिया गया। अंक 8, जो वर्तमान जांच के लिए एकमात्र प्रासंगिक मुद्दा है, पढ़ता है;

"क्या लम्बरदार सरकार की सेवा में एक व्यक्ति है या यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (7) के किसी भी खंड के अंतर्गत आता है?"

चुनाव न्यायाधिकरण ने दोनों प्रारंभिक मुद्दों पर प्रतिवादी के खिलाफ फैसला सुनाया। मुद्दे 8 पर यह माना गया कि अधिनियम की धारा 123 की उपधारा (7) के खंड (एफ) के अर्थ के तहत एक लंबरदार सरकार की सेवा में एक राजस्व अधिकारी और ग्राम लेखाकार था। प्रारंभिक मुद्दों पर निष्कर्षों के आधार पर, ट्रिब्यूनल ने निर्देश दिया कि शेष मुद्दों को सुनवाई के लिए निर्धारित किया जाए। प्रतिवादी ने संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत चंडीगढ़ में पंजाब उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके उस आदेश की शुद्धता का प्रचार किया। इस याचिका पर पंजाब उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने सुनवाई की, जिसमें न्यायमूर्ति फलशॉ और मेहर सिंह शामिल थे। विद्वान न्यायाधीशों ने 12 मार्च, 1959 के अपने आदेश द्वारा 3 वें मुद्दे पर चुनाव न्यायाधिकरण के आदेश की पुष्टि की, लेकिन 8 वें मुद्दे पर उसके आदेश को रद्द कर दिया। विद्वान न्यायाधीशों ने कहा कि "लाम्बरदार निस्संदेह सरकार द्वारा भूमि राजस्व एकत्र करने और ऐसा करने के लिए अपने पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त राशि पर एक वैधानिक

प्रतिशत प्राप्त करने के उद्देश्य से नियुक्त राजस्व अधिकारियों का एक वर्ग है, लेकिन जबकि उन्हें ग्राम लेखाकारों के साथ शामिल किया गया था, जिन्हें इस राज्य में पटवाड़ी कहा जाता है और भारत के अन्य हिस्सों में धारा में निर्धारित अन्य नामों से, उन्हें खंड (एफ) के प्रावधानों द्वारा स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है।" यद्यपि इस निष्कर्ष का दायरा कुछ विवाद का विषय था, लेकिन यह स्पष्ट है कि विद्वान न्यायाधीशों का यह मानना था कि यद्यपि 1956 में संशोधन किए जाने से पहले अधिनियम की धारा 123 की संबंधित उप-धारा (8) के तहत एक लम्बरदार को अयोग्य ठहराया गया था, लेकिन उसे संशोधित धारा की उप-धारा (7) के खंड (च) द्वारा उस धारा के संचालन से बाहर रखा गया था। उस निष्कर्ष के आधार पर, उच्च न्यायालय ने मुद्दे 8 पर न्यायाधिकरण के फैसले को दरकिनार कर दिया और अन्य मामलों में इसकी पुष्टि की। अपीलार्थी ने इस न्यायालय की विशेष अनुमति प्राप्त करके वर्तमान अपील दायर की।

अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री एन.सी. चटर्जी का तर्क है कि कानून की धारा 123 की उप-धारा (7) के खंड (च) के अर्थ के भीतर एक लम्बरदार एक राजस्व अधिकारी और ग्राम लेखाकार दोनों होता है, और इसलिए, प्रत्यर्थी अपने निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न केंद्रों के लिए अपने गिनती और मतदान एजेंटों के रूप में लम्बरदारों को शामिल करने में, एक भ्रष्ट प्रथा का दोषी था। दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील श्री पाठक का तर्क है कि उक्त खंड के अर्थ के भीतर एक लम्बरदार न तो राजस्व अधिकारी है और न ही ग्राम लेखाकार है।

उठाया गया प्रश्न अधिनियम की धारा 123 के प्रासंगिक प्रावधानों पर निर्भर करता है। उक्त खंड में लिखा हैः

> "धारा 123 भ्रष्ट आचरण-निम्नलिखित को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भ्रष्ट आचरण माना जाएगाः -

*   *   *

(7) किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कोई सहायता (वोट देने के अलावा) प्राप्त करना या प्राप्त करना या प्राप्त करने के लिए उकसाना, सरकार की सेवा में किसी भी व्यक्ति से और निम्नलिखित वर्गों में से किसी से संबंधित, अर्थात्ः

(च) ग्राम लेखाकारों सहित राजस्व अधिकारी, जैसे कि पटवारियां, लेखपाल, तलाटी, कर्णम और इसी तरह के, लेकिन अन्य ग्राम अधिकारियों को छोड़कर।

स्पष्टीकरण-(1) इस धारा में "अभिकर्ता" पद में एक चुनाव अभिकर्ता, एक मतदान अभिकर्ता और कोई भी व्यक्ति शामिल है जिसने उम्मीदवार की सहमति से चुनाव के संबंध में एक अभिकर्ता के रूप में कार्य किया है।

(2) खंड (7) के प्रयोजनों के लिए, एक व्यक्ति को उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में सहायता करने वाला माना जाएगा यदि वह एक चुनाव एजेंट, या एक मतदान एजेंट, या उस उम्मीदवार के एक गिनती एजेंट के रूप में कार्य करता है।"

इस धारा के तहत, जहां तक वर्तमान जांच के लिए सामग्री है, कोई उम्मीदवार किसी व्यक्ति को अपने चुनाव एजेंट के रूप में नियुक्त नहीं कर सकता है यदि ऐसा व्यक्ति सरकार की सेवा में है और उप-धारा (7) के घ. (च) द्वारा शासित अधिकारियों में से एक है, तो अयोग्य अधिकारी होने के लिए एक लम्बरदार न केवल सरकार की सेवा में होना चाहिए बल्कि अधिनियम की धारा 123 की उप-धारा (7) के खंड (च) के अर्थ के

भीतर राजस्व अधिकारी होना चाहिए। यदि वह उक्त उप-धारा के खंड (च) के अर्थ के भीतर राजस्व अधिकारियों में से एक नहीं था, तो यह सवाल विचार के लिए उत्पन्न नहीं होगा कि क्या वह सरकार की सेवा में था। इसलिए, हम इस बात पर विचार करने के लिए आगे बढ़ेंगे कि क्या कोई लम्बरदार अधिनियम की धारा 123 की उप धारा (7) के खंड (च) के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों में से एक है।

अधिनियम की धारा 123 की उप-धारा (7) के खंड (च) में अधिकारियों की तीन श्रेणियों का उल्लेख है, अर्थात् (i) राजस्व अधिकारी; (ii) ग्राम लेखाकार; और (iii) अन्य ग्राम अधिकारी। वे कौन से अधिकारी हैं जो इन श्रेणियों में से प्रत्येक के अंतर्गत आते हैं?

(i) राजस्व अधिकारीः राजस्व अधिकारी अधिकारियों का एक प्रसिद्ध वर्ग है जिन्हें विभिन्न राज्यों के राजस्व प्रशासन का जिम्मा सौंपा गया है, हालांकि राज्य से राज्य में उन्हें दिए गए नामकरण और पदनामों के संबंध में कुछ भिन्नताएं हैं। इनमें एक पदानुक्रम होता है जिसमें राजस्व बोर्ड या शीर्ष पर एक आयुक्त और सबसे नीचे ग्राम अधिकारी होते हैं। बेडेन पॉवेल ने अपनी पुस्तक "लैंड-सिस्टम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया", खंड 1 में पृष्ठ 323 पर आम तौर पर ब्रिटिश भूमि प्रशासन की मशीनरी का वर्णन किया है। वे उन विभिन्न अधिकारियों की ओर इशारा करते हैं जो राज्य, जिला, तालुक और ग्राम स्तर पर विभिन्न राज्यों में राजस्व प्रशासन के प्रभारी हैं। वे विभिन्न राज्यों के लिए अलग-अलग अध्याय आवंटित करते हैं और प्रत्येक राज्य में राजस्व प्रशासन के विभिन्न अंगों का बारीकी से वर्णन करते हैं। पंजाब राज्य में आते हुए, वह निम्नलिखित पदों के साथ राजस्व अधिकारियों का वर्णन करते हैंः वित्तीय आयुक्त, भूमि अभिलेख और कृषि निदेशक, आयुक्त, उपायुक्त (कलेक्टर), अधीनस्थ अधिकारी, तहसील अधिकारी और ग्राम अधिकारी। अन्य राज्यों में मामूली भिन्नताओं के साथ एक ही पैटर्न प्रचलित है। इसलिए, यह बिना किसी विरोधाभास के माना जा सकता है कि एक

राजस्व अधिकारी वह है जो राजस्व के व्यवसाय में कार्यरत है, और यह शब्द राज्य के राजस्व प्रशासन में पदानुक्रम की श्रृंखला में ऐसे सभी राजस्व अधिकारियों को लेने के लिए पर्याप्त व्यापक है।

इस मामले में इस सवाल पर हमारी राय व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या किसी राज्य या संघ की सेवा में अधिकारी, जो भूमि राजस्व के प्रभारी नहीं हैं, लेकिन राजस्व के अन्य स्रोतों जैसे सीमा शुल्क, आय-कर या इसी तरह से जुड़े हैं, "राजस्व अधिकारियों" की श्रेणी में आते हैं।

(ii) ग्राम लेखाकारः अधिनियम की धारा 123 की उप-धारा (7) के खंड (च) में अधिकारियों का दूसरा समूह ग्राम लेखाकार हैं, जैसे कि पटवाड़ी, लेखपाल, तलाटी कर्णम आदि। गणना किए गए अधिकारियों के कार्यों के सावधानीपूर्वक अध्ययन से पता चलता है कि वे केवल एक पटवारी के स्थानीय समकक्ष हैं। खंड (च) स्वयं "ग्राम लेखाकार" शब्दों के अर्थ का पता लगाने के लिए शब्दकोश प्रदान करता है। "ग्राम लेखाकार" शब्दों के तुरंत बाद "जैसे" वाक्यांश और गणना किए गए अधिकारियों के बाद "जैसे" वाक्यांश इंगित करते हैं कि उदाहरणों का उद्देश्य चित्रण द्वारा एक परिभाषा प्रदान करना है। इसे अलग तरह से रखने के लिए, अधिकारियों की गणना की गई श्रेणियां और इसी तरह के शब्द "ग्राम लेखाकार" की सामग्री और अर्थ को सटीक रूप से इंगित करते हैं।

(iii) अन्य ग्राम अधिकारीः अन्य ग्राम अधिकारी स्पष्ट रूप से ग्राम लेखाकारों के अलावा ग्राम अधिकारी होते हैं। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि राजस्व अधिकारियों के मामले में, जिनके अधिकार क्षेत्र केवल संबंधित गाँवों तक ही सीमित नहीं है, के विपरीत, इस श्रेणी के अधिकारी गाँव के भीतर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वालों तक ही सीमित हैं।

यह एक प्राथमिक नियम है कि एक खंड का निर्माण सभी भागों को एक साथ किया जाना है न कि केवल एक भाग का, और उस वाक्यांश का अर्थ व्याकरण के नियमों के अनुसार लगाया जाना है। अतः इस खंड का अर्थ काफी स्पष्ट है। वंश "राजस्व अधिकारी" है, और "सहित" और "संयोजन द्वारा जुड़े खंडों को छोड़कर" लेकिन "यह दर्शाता है कि ग्राम लेखाकार राजस्व अधिकारियों के समूह में शामिल हैं, लेकिन अन्य ग्राम अधिकारियों को इससे बाहर रखा गया है। यदि एक्स में ए शामिल है लेकिन बी शामिल नहीं है, तो इसका सीधा सा मतलब यह हो सकता है कि एक्स ए को लेता है लेकिन बी को बाहर निकालता है। इस मामले में यह विचार करना आवश्यक नहीं है कि क्या समावेशी परिभाषा "राजस्व अधिकारी" शब्दों के अर्थ को बढ़ाती है, या उन्हें स्पष्ट और स्पष्ट बनाती है, अर्थात, कि गणना किए गए अधिकारी "राजस्व अधिकारियों" के दायरे में हैं। क्योंकि किसी भी निर्माण में ग्राम लेखाकार राजस्व अधिकारी होंगे। लेकिन हम इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि जिसे बाहर रखा गया है वह उस का हिस्सा नहीं था जिससे इसे बाहर रखा गया है, और यह कि लम्बरदार राजस्व अधिकारी नहीं थे और फिर भी उन्हें प्रचुर सावधानी के साथ बाहर रखा जाना था। यदि ऐसा है, तो इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम अधिकारियों, जिनमें लम्बरदार भी शामिल थे, को राजस्व अधिकारियों के समूह से बाहर रखा गया था, जिसके परिणामस्वरूप वे उक्त खंड के प्रावधानों द्वारा लगाए गए अयोग्यता से मुक्त हो जाते हैं।

लेकिन यह कहा जाता है कि यह निर्माण "राजस्व अधिकारी" शब्दों और "अन्य ग्राम अधिकारियों को छोड़कर" शब्दों को अनावश्यक बना देगा, क्योंकि, वही परिणाम केवल "ग्राम लेखाकार, जैसे, पटवारी, लेखपाल, तलाटी, कर्णम और इसी तरह" को लागू करके प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम ऐसा कहें तो यह तर्क "राजस्व अधिकारी" और "ग्राम अधिकारी" शब्दों के बीच के अंतर को नजरअंदाज कर देता है। राजस्व

अधिकारी", जैसा कि हमने बताया है, एक अधिक व्यापक शब्द है और उन सभी अधिकारियों को लेता है जो राजस्व व्यवसाय में कार्यरत हैं, जबकि ग्राम अधिकारियों का अधिकार क्षेत्र उनके संबंधित गांवों तक ही सीमित है। ग्राम अधिकारी राजस्व अधिकारियों की सामग्री को समाप्त नहीं करते हैं, और उनके बहिष्कार के बाद भी उच्च स्तर पर कई राजस्व अधिकारी होंगे जो खंड (च) द्वारा शासित होंगे यदि यह निर्माण है, तो खंड में उपयोग किए गए प्रत्येक शब्द को एक अर्थ दिया जाता है और कोई भी शब्द अधिशेष नहीं बन जाता है।

आइए अब हम अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील द्वारा सुझाए गए खंड की अन्य दो व्याख्याओं की शुद्धता का परीक्षण करें। सबसे पहले, यह तर्क दिया जाता है कि पहले के अधिनियम में गिने गए अधिकारियों की लंबी सूची को देखते हुए "ग्राम अधिकारी" शब्दों का उपयोग बहुत सावधानी से किया जाता है, ताकि जनता "पसंद" शब्द की व्याख्या इस तरह से कर सके कि सभी ग्राम अधिकारी जो राजस्व अधिकारी नहीं हैं। इस तर्क को स्वीकार करना विधानमंडल पर सटीकता की कमी का आरोप लगाना है। "राजस्व अधिकारी" शब्द, चाहे वे किसी भी अर्थ में उपयोग किए जाएं, स्पष्ट रूप से उन अधिकारियों को नहीं समझ सकते हैं जो राजस्व अधिकारी नहीं हैं, और उस स्थिति में ऐसे अधिकारियों को राजस्व अधिकारियों के समूह से बाहर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपवर्जन का विधायी साधन केवल संपूर्ण से एक भाग को बाहर करने के लिए अपनाया जाता है, जो, लेकिन अपवर्जन के लिए, इसका हिस्सा बना हुआ है। इस व्याख्या को अस्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें उन शब्दों की पहचान शामिल है जो अधिशेष हैं।

न ही वैकल्पिक निर्माण का कोई उच्च गुण है। जाति, तर्क आगे बढ़ता है, गाँव के लेखाकार हैं, और बहिष्कार केवल गाँव के लेखाकारों की श्रेणी से है। यह संरचना दो दोषों से ग्रस्त है। सबसे पहले, गाँव के अधिकारी "गाँव के लेखाकार" वंश से बनी

प्रजाति नहीं हो सकते हैं, क्योंकि "गाँव के अधिकारी" शब्दों का अर्थ "गाँव के लेखाकार" शब्दों की तुलना में व्यापक है। इस व्याख्या को स्वीकार करने के लिए "ग्राम लेखाकारों" को "ग्राम अधिकारियों" के रूप में पढ़ना है। दूसरा, यदि शब्दों को इस तरह प्रतिस्थापित किया जाता है, तो "ग्राम अधिकारी" और "अन्य ग्राम अधिकारी" शब्दों के दोनों समूह अधिशेष हो जाते हैं, क्योंकि एक ही परिणाम केवल "गणना किए गए अधिकारियों सहित राजस्व अधिकारियों को अधिनियमित करके प्राप्त किया जा सकता है; क्योंकि विद्वान वकील के अनुसार, समावेशी खंड का उद्देश्य केवल गणना किए गए अधिकारियों को लाना है। इस व्याख्या को इस कारण से भी अस्वीकार किया जाना चाहिए कि इसकी स्वीकृति में खंड का पुनर्लेखन और उसमें अनावश्यक शब्दों की मान्यता शामिल है। इसमें एक ऐसी श्रेणी से कुछ को बाहर करना भी शामिल है। जिसमें पूर्व परिकल्पना शामिल नहीं है; उस दृष्टिकोण में बहिष्कार पूरी तरह से निरर्थक है।

अपीलार्थी के विद्वान वकील ने राजा बहादुर के.सी. देव भंज बनाम रघुनाथ मिश्रा [(1)] 19 ई.एल.आर.। मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया और तर्क दिया कि इस न्यायालय ने उस व्याख्या को स्वीकार कर लिया है जिसे वह खंड (च) पर रखना चाहता है। उस मामले में यह सवाल उठाया गया था कि क्या उड़ीसा ग्राम पंचायत अधिनियम, 1948 के तहत गठित ग्राम पंचायत का सरपंच उड़ीसा राज्य सरकार की सेवा में एक व्यक्ति था। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पंच अधिनियम की धारा 123 (7) (च) के अर्थ में सरकार की सेवा में कार्यरत व्यक्ति नहीं था। यह निष्कर्ष अपील का निपटारा करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन न्यायालय ने इस वैकल्पिक तर्क पर भी विचार किया कि भले ही सरपंच सरकार की सेवा में कोई व्यक्ति हो, वह उक्त उप-धारा के खंड (च) के दायरे में आने वाले अधिकारियों में से एक नहीं था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उक्त खंड के अर्थ के भीतर सरपंच न तो

राजस्व अधिकारी था और न ही ग्राम लेखाकार। लेकिन निर्णय के दौरान उक्त खंड के निर्माण के संबंध में कुछ टिप्पणियां की गईं, जिन पर अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया जाता है। प्रासंगिक अवलोकन पृष्ठ 596 पर पाए जाते हैं, और वे इस प्रकार हैंः

> "खंड (च), पहली बार में, सरकार की सेवा में एक ऐसे व्यक्ति की बात करता है जो एक राजस्व अधिकारी है और फिर वर्ग का विस्तार ग्राम लेखाकारों तक करता है। "पटवारियाँ, लेखफल, तलाटी, कर्णम आदि" शब्द केवल "ग्राम लेखाकारों सहित राजस्व अधिकारी" शब्दों के वर्णनात्मक हैं। खंड (च) के तहत यह आवश्यक है कि सरकार की सेवा में कोई व्यक्ति राजस्व अधिकारी या ग्राम लेखाकार होना चाहिए, चाहे वह अधिकारी या ग्राम लेखाकार किसी भी नाम से वर्णित हो। खंड (च) के प्रावधानों से प्रत्येक अन्य ग्राम अधिकारी का अपवर्जन इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मजबूर करता है कि इस खंड के उड़ीसा अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत के एक सरपंच पर लागू होने से पहले यह साबित किया जाना चाहिए कि वह या तो एक राजस्व अधिकारी है या एक ग्राम लेखाकार है।"

यह तर्क दिया जाता है कि उक्त टिप्पणियों से पता चलता है कि इस न्यायालय ने खंड (च) की शर्तों की व्याख्या हमारे द्वारा बताए गए तरीके से अलग तरीके से की है। जबकि हमने माना है कि 'जैसे आदि' और 'जैसे' शब्द केवल ग्राम लेखाकारों के लिए वर्णनात्मक हैं, ऊपर निकाली गई टिप्पणियों से पता चलता है कि उक्त शब्द "ग्राम लेखाकारों सहित राजस्व अधिकारियों" की समग्र अभिव्यक्ति के वर्णनात्मक हैं। उस दृष्टिकोण में भी, हम यह नहीं सोचते हैं कि खंड को छोड़कर केवल ग्राम लेखाकारों को संदर्भित करता है और राजस्व अधिकारियों को नहीं। विद्वान न्यायाधीश एक सरपंच से

संबंधित थे, और उनका मानना था कि वह गाँव का अधिकारी नहीं था। यदि वह ग्राम अधिकारी नहीं था, तो उसे खंड में राजस्व अधिकारियों की श्रेणी से बाहर नहीं किया गया था, और इसलिए, उक्त खंड उस पर लागू होगा यदि वह राजस्व अधिकारी या ग्राम लेखाकार था। इसलिए, जब विद्वान न्यायाधीशों ने कहा कि यह साबित किया जाना चाहिए कि खंड उनके ऊपर लागू होने से पहले एक राजस्व अधिकारी या एक ग्राम लेखाकार था, तो उन्होंने उस खंड के अर्थ के भीतर राजस्व अधिकारियों के अर्थ में "राजस्व अधिकारी" शब्दों का उपयोग किया होगा, अर्थात्, अन्य ग्राम अधिकारियों को छोड़कर राजस्व अधिकारी। वह निर्णय वास्तव में अपवर्जन खंड की व्याख्या पर आगे नहीं बढ़ा, लेकिन इस आधार पर आगे बढ़ा कि उस मामले का सरपंच पहली बार में सरकार की सेवा में नहीं था और दूसरी बात यह कि वह अधिनियम के अर्थ के भीतर एक राजस्व अधिकारी नहीं था, क्योंकि वह राजस्व कार्य नहीं करता था और न ही वह एक ग्राम लेखाकार था। उल्लिखित कारणों से, हम इस धारा में उपयोग किए गए शब्दों के स्पष्ट अर्थ को स्वीकार करते हुए मानते हैं कि ग्राम राजस्व अधिकारी होने के नाते, लैम्बरदार को अधिनियम की धारा 123 की उप धारा (7) के खंड (च) के संचालन से बाहर रखा गया है।

यह हमें इस सवाल पर विचार करने की ओर ले जाता है कि क्या एक लैम्बरदार उक्त खंड के अर्थ के भीतर एक ग्राम लेखाकार है।

हमारे देश के प्रारंभिक काल से ग्राम प्रशासन का इतिहास हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग नामों से जाने जाने वाले मुखिया और पटवारियों के बीच स्थिति और कार्यों के स्पष्ट सीमांकन को दर्शाता है। जहाँ तक पंजाब राज्य का संबंध है, यह आम बात है कि गाँव के मुखिया को हमेशा से लम्बरदार के रूप में वर्णित किया गया है। बेडेन पॉवेल ने अपनी पुस्तक "लैंड-सिस्टम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया", खंड 1 में पृष्ठ 21 पर एक गाँव के मुखिया का वर्णन किया हैः

"एक बार फिर, मैं अंग्रेजी शब्द हेडमैन का उपयोग उस व्यक्ति को इंगित करने के लिए कर सकता हूं जो गाँव के कार्यकाल के कुछ रूपों में समुदाय का एक अनिवार्य हिस्सा है, कुछ विचार का एक वंशानुगत अधिकारी है। जहाँ ऐसा व्यक्ति गाँव के सामाजिक संविधान के लिए आवश्यक नहीं है, वहाँ भी सरकार ने आम तौर पर किसी न किसी रूप में एक मुखिया को नियुक्त या मान्यता दी है, क्योंकि एक व्यक्ति के साथ व्यवहार करना और उसे संचार का माध्यम और प्रतिनिधि बनाना अधिक सुविधाजनक है।"

एक पटवारियों के बारे में बात करते हुए, विद्वान लेखक पृष्ठ 22 पर कहते हैंः

"एक अन्य बहुत ही आम भारतीय राजस्व शब्द है "पटवार", जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जो गाँव के खातों को रखता है, और सबसे बढ़कर, अधिकारों के मानचित्रों और अभिलेखों की देखभाल करता है, और भूमि स्वामित्व और किरायेदारी में परिवर्तन को पंजीकृत करता है। कुछ पुस्तकें उन्हें 'ग्राम लेखाकार', अन्य 'ग्राम पंजीयक' कहती हैं; लेकिन दोनों में से कोई भी शब्द संतोषजनक नहीं है। " पटवारियों (उत्तरी भारत और मध्य प्रांतों में) के समानार्थी नाम दक्षिण में 'कर्णम' और पश्चिम में 'कुलकर्णी' है।

उक्त पुस्तक के खंड 2 में, विद्वान लेखक ने पृष्ठ 740 पर पंजाब में एक लम्बरदार और एक पटवारी का निम्नलिखित शब्दों में वर्णन किया हैः

"पंजाब में मुखिया को 'लम्बरदार' कहा जाता है। जितने, यदि अधिकांश नहीं, तो गाँवों में कई खंड होते हैं, आमतौर पर कई 'लम्बरदार' होते हैं, और इस प्रकार एक व्यक्ति द्वारा कई सह-भागीदारों

के प्रतिनिधित्व का लाभ कुछ हद तक खो जाता है। इसलिए, यह आवश्यक माना जाता है कि कई प्रतिनिधियों के लिए एक प्रतिनिधि के रूप में, एक एकल प्रमुख हो, जिसके साथ संवाद करना आसान हो और जिसे जिम्मेदार ठहराया जा सके।"

पटवारियों के साथ व्यवहार करते हुए, विद्वान लेखक पृष्ठ 733 पर कहते हैं:

"यह अधिकारी व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके विधिवत प्रशिक्षित होने और गाँव के अभिलेखों और आंकड़ों को सावधानीपूर्वक तैयार करने में सक्षम होने पर, वास्तव में (अंतिम उपाय में) लोगों के श्रम और परेशानी को कम करने की उम्मीद पर निर्भर करता है जो निपटान कार्यवाही की पुनरावृत्ति के अवसरों पर होती है।"

विद्वान लेखक पृष्ठ 735 में पटवारियों के अन्य कर्तव्यों का उल्लेख करते हैं। पटवारियों का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य वार्षिक भूमि-अभिलेख तैयार करना और उनका रखरखाव करना है। ऐतिहासिक रूप से, इसलिए, इन दो श्रेणियों के अधिकारियों की स्थिति और कार्यों के बीच एक स्पष्ट सीमांकन है।

पंजाब में भी इसी तरीके का पालन किया गया। सर जेम्स मैक द्वारा संकलित पंजाब भूमि प्रशासन नियमावली। डूई, जिसे इस विषय पर एक मानक पुस्तक माना जाता है, गाँव के मुखिया और एक पटवारियों की प्रकृति और संबंधित कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन करती है। अध्याय 8 गाँव के मुखिया के कर्तव्यों से संबंधित है। ग्राम प्रधान का राज्य के साथ अपने संबंधों में सरकार और भूमि-मालिकों और भूमि के किरायेदारों के प्रति कर्तव्य होता है। सरकार के प्रति उनके कर्तव्य इस प्रकार हैं:

ए. 1. भूमि राजस्व और भूमि राजस्व के रूप में वसूली योग्य सभी राशियों को एकत्र करना और खजाने में जमा करना।

2. तहसीलदार को रिपोर्ट करना-

(क) समनुदेशकों और पेंशनभोगियों की मृत्यु और एक वर्ष से अधिक समय से उनकी अनुपस्थिति;

(ख) सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण या नुकसान।

3. सहायता करना-

(क) फसल निरीक्षण, सर्वेक्षण, उत्परिवर्तन के अभिलेख और अन्य राजस्व व्यवसाय करने में;

(ख) सैनिकों और सरकारी अधिकारियों के लिए भुगतान, आपूर्ति या परिवहन के साधन प्रदान करने में।

बी. भूमि मालिकों और संपत्ति के किरायेदारों के लिए कर्तव्यः

1. उनसे प्राप्त प्रत्येक भुगतान को उनकी पार्चा पुस्तकों में स्वीकार करना।

2. सामान्य ग्राम निधि (मालबा) का संग्रह और प्रबंधन करना, और सभी प्राप्तियों और व्यय के लिए शेयरधारकों को लेखा देना-(1953 से लैम्बरदार को इस कर्तव्य से मुक्त कर दिया गया है, क्योंकि वर्तमान में कोई सामान्य भूमि नहीं है।)

मुखिया के अन्य मुख्य कर्तव्यों में से एक अपराध की रोकथाम और पता लगाने में सहायता करना है।

उक्त नियमावली के अध्याय VII में एक पटवारियों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। उनके तीन मुख्य कर्तव्य हैंः

(1) प्रत्येक फसल में उगाई गई फसलों के रिकॉर्ड का रखरखाव;

(2) उत्परिवर्तन के समयबद्ध रिकॉर्ड द्वारा अधिकारों के रिकॉर्ड को अद्यतन रखना; और

(3) फसल निरीक्षण, उत्परिवर्तन के रजिस्टर और अधिकारों के रिकॉर्ड से प्राप्त जानकारी को शामिल करते हुए सांख्यिकीय विवरणों की सटीक तैयारी।

उक्त नियमावली के अध्याय 11 में एक पटवारियों द्वारा रखे गए रजिस्टरों के विवरण का वर्णन किया गया है। वे हैंः

(1) क्षेत्र विवरण या मिलन रक्बा।

(2) खरिफ फसल विवरण या जिन्सवार।

(3) रबी फसल विवरण या जिन्सवार।

(4) राजस्व खाता या जमा वसील बाकी।

(5) मालिकों और अधिभोग किरायेदारों के अधिकारों के हस्तांतरण का विवरण।

(5-(क) भूमि के वर्गों के स्वामित्व की बिक्री और बंधक का विवरण।

(6) स्वामित्व, बंधक और राजस्व असाइनमेंट का विवरण।

(7) कृषि अधिभोग के विवरण।

(8) किरायेदारों द्वारा अपनी इच्छानुसार भुगतान किए गए किराए का विवरण।

(9) कृषि स्टॉक का विवरण।

ग्राम प्रधान और पटवारियों के संबंधित कर्तव्यों के बेहतर विवरण के लिए, पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 (1887 का अधिनियम XVII) और उसके तहत बनाए गए नियमों, विशेष रूप से इसके 20 और पंजाब भूमि अभिलेख नियमावली के अध्याय III के प्रावधानों का आसानी से उल्लेख किया जा सकता है।

ग्राम प्रधान और एक पटवारियों के संबंधित कर्तव्यों का तुलनात्मक अध्ययन दोनों के बीच के अंतर को सामने लाता है, अर्थात्, पहला न केवल गाँव में राज्य का एक प्रतिनिधि है, बल्कि गाँव का मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि भी है, और दूसरा एक तुलनात्मक रूप से छोटा अधिकारी है जिसे राजस्व व्यवसाय से संबंधित खातों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों को बनाए रखने का कर्तव्य सौंपा गया है।

इस पृष्ठभूमि के साथ संसद ने अधिनियम की धारा 123 को मूल रूप से धारा 123(8) पारित किया, जो अधिनियम की धारा 123(7) के अनुरूप थी, इस प्रकार पढ़ें;

> "123.प्रमुख भ्रष्ट आचरण.-इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित को भ्रष्ट आचरण माना जाएगा,
>
> (8) किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता की मिलीभगत से, भारत सरकार या किसी अन्य राज्य की सरकार के तहत सेवारत किसी भी व्यक्ति से उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कोई सहायता प्राप्त करना या प्राप्त करना या प्राप्त करने का प्रयास करना।
>
> स्पष्टीकरणः इस खंड के प्रयोजनों के लिए-
>
> (क) भारत सरकार के अधीन सेवा करने वाले व्यक्ति में ऐसा कोई व्यक्ति शामिल नहीं होगा जिसे केंद्र सरकार द्वारा ऐसा व्यक्ति घोषित किया गया हो जिसके लिए इस खंड के प्रावधान लागू नहीं होंगे।
>
> (ख) किसी भी राज्य की सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति में उस राज्य में नियोजित, चाहे वह पद पूर्णकालिक अधिकारी हो या न

हो, एक पटवार, चौकीदार, दफेदार, ज़ैलदार, शानबाग, कर्णम, तलाती, तलारी, पाटिल, ग्राम मुनीफ, ग्राम प्रधान या कोई अन्य ग्राम अधिकारी शामिल होगा, लेकिन इसमें कोई भी व्यक्ति (उपरोक्त किसी भी ग्राम अधिकारी के अलावा) शामिल नहीं होगा जिसे राज्य सरकार द्वारा एक व्यक्ति घोषित किया गया है जिसे इस खंड के प्रावधान लागू नहीं होंगे।"

इस धारा के तहत, सरकार के तहत सेवारत किसी भी व्यक्ति से सहायता प्राप्त करना एक भ्रष्ट प्रथा थी, और सभी ग्राम अधिकारियों को समावेशी परिभाषा के अनुसार, सरकार के तहत सेवारत व्यक्ति घोषित किया गया था। इस अनुभाग में दिए गए ग्राम अधिकारियों की सूची में एक पटवाड़ी और इसी तरह के अधिकारी और एक ग्राम प्रधान और इसी तरह के अधिकारी भी शामिल थे। संसद को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों के लिए, उस धारा को 1956 में संशोधित किया गया था। 1956 में संशोधित धारा 123 (7) (च) पहले ही निकाली जा चुकी है। इस खंड के तहत, ग्राम लेखाकारों जैसे पटवारियों आदि के अलावा ग्राम अधिकारियों को राजस्व अधिकारियों की परिभाषा से बाहर रखा गया था। जब संसद, दो श्रेणियों के अधिकारियों के बीच स्पष्ट अंतर की जानकारी के साथ, राजस्व अधिकारियों की परिभाषा के भीतर एक को स्पष्ट रूप से शामिल करती है और अन्य ग्राम अधिकारियों को इससे बाहर करती है, तो खंड का इस तरह से अर्थ लगाना अनुचित होगा कि ग्राम प्रधान को ग्राम लेखाकार की श्रेणी में शामिल किया जाए। यह खंड में उपयोग की गई भाषा के साथ हिंसा करना होगा; क्योंकि, खंड में परिभाषित "ग्राम लेखाकार" शब्दों ने परंपरा और कानून द्वारा एक द्वितीयक अर्थ प्राप्त कर लिया है।

ऐसा कहा जाता है कि चुनाव के मामले में एक पटवारियों को अयोग्य ठहराने और एक मुखिया को योग्य बनाने का कोई तार्किक आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि

तर्क आगे बढ़ता है कि एक मुखिया का मतदाता पर एक पटवारियों की तुलना में अधिक प्रभाव होता है। यह न्यायालय कानून में अंतर्निहित नीति से संबंधित नहीं है, बल्कि केवल संसद के व्यक्त इरादे से संबंधित है। धारा 123 की उप-धारा (7) के खंड (च) को 1958 के अधिनियम 58 द्वारा संशोधित किया गया था और संशोधित खंड इस प्रकार हैः

> "धारा 123 (7)(च): लम्बरदार, मालगुजर, पटेल, देशमुख या किसी अन्य नाम से जाने जाने वाले ग्राम राजस्व अधिकारियों के अलावा राजस्व अधिकारी, जिनका कर्तव्य भूमि राजस्व एकत्र करना है और जिन्हें उनके द्वारा एकत्र किए गए भूमि राजस्व की राशि के हिस्से या कमीशन द्वारा पारिश्रमिक दिया जाता है, लेकिन जो किसी भी पुलिस कार्य का निर्वहन नहीं करते हैं।"

संशोधित खंड के तहत, लांबारदारों को स्पष्ट रूप से "राजस्व अधिकारियों" की परिभाषा से बाहर रखा गया है। हम इस नवीनतम संशोधन का उल्लेख खंड के निर्माण में सहायता के रूप में नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस तर्क को पूरा करने के लिए कर रहे हैं कि उक्त दो श्रेणियों के ग्राम अधिकारियों के बीच अंतर के लिए कोई नीति अंतर्निहित नहीं हो सकती थी। तथ्य यह है कि संसद ने अपने नवीनतम संशोधन में प्रथम दृष्टया इस अंतर को बनाए रखा है, यह एक संकेत हो सकता है कि उसके विचार में एक लम्बरदार और ग्राम लेखाकार के बीच प्रासंगिक अंतर है। इसलिए हम यह मानेंगे कि किसी ग्राम प्रधान को उक्त खंड में "समान" शब्दों के भीतर नहीं लाया जा सकता है।

इस दृष्टिकोण से, इस सवाल पर हमारी राय व्यक्त करना आवश्यक नहीं है कि क्या एक लम्बरदार अधिनियम की धारा 123 (7) के अर्थ के भीतर सरकार की सेवा में एक व्यक्ति है।

इस मामले से अलग होने से पहले, हमें अपनी भावना व्यक्त करनी चाहिए कि चुनाव याचिका के अंतिम निपटारे में इतनी देर नहीं होनी चाहिए थी। चुनाव 24 फरवरी, 1957 को हुए थे, प्रतिवादी को 25 फरवरी, 1957 को निर्वाचित घोषित किया गया था और चुनाव 11 अप्रैल, 1957 को दायर किया गया था। हालाँकि ढाई साल बीत चुके हैं, लेकिन याचिका का अभी तक अंतिम रूप से निपटारा नहीं किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि अन्य मुद्दों पर चुनाव याचिका का जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा।

नतीजतन, अपील विफल हो जाती है और लागत के साथ खारिज कर दी जाती है।

याचिका खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक हेमन्त सोनी द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।